

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) Yes.

(b) It has been reported by DDA that on the night of 12.3.84 at about 9-00 P.M. three workers (2 male and 1 female) were assigned by the contractor to clean the septic tank in Block A, Jahangir Puri. One of the workers who was cleaning the septic tank by taking out sludge through a man-hole with the help of a bucket, was reported to have slipped into the manhole. He could not come out of the septic tank. Another person was then reported to have entered the septic tank to rescue him. He too did not come out. Therefore, the third worker, who had been called to the site by the lady worker, tried to take out the two persons, but to no avail. Thereafter, some more persons were reported to have entered the septic tank and ultimately succeeded in taking out the three trapped persons. All the affected persons were immediately rushed to Hindu Rao Hospital, with the help of local residents. The doctor on duty in Hindu Rao Hospital, pronounced the three persons as dead. The other three were admitted for treatment. The names of three casualties has been given as :

1. Shri Chumbadia
2. Shri Remnua
3. Shri Ramesh.

The survivors who were hospitalised for treatment has since been discharged from the hospital.

(c) The Lt.-Governor of Delhi sanctioned ex-gratia payment of Rs. 5,000 to the next kin of each the three workers who died while cleaning the septic tank, on compassionate grounds.

कृषि के विकास के लिए हिमालयन अलपाइन इन्स्टीट्यूट की स्थापना

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमालयन क्षेत्र में कृषि तथा उससे संबद्ध क्षेत्रों के विकास की संभावनाओं का पता लगाने के लिये उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में मुनसियारी में उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के सहयोग से एक हिमालयन अलपाइन इन्स्टीट्यूट स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संस्थान का पूरा व्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) से (ग) गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के सहयोग से उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले के मनस्यारी में हिमालय अलपाइन संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को एक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र की स्थापना में, जिसकी सहायक के लिए 1-2 अनुसंधान उप-केन्द्रों की स्थापना की जाएगी, सहायता देने पर सहमत हो गया है, जो हिमालय क्षेत्र में आठ जिलों के लिए कार्य करेगा। मुख्य क्षेत्रीय केन्द्र को रानीचौरी (टिहरी गढ़वाल) में स्थापित करने का प्रस्ताव है तथा चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जिलों के एक उपयुक्त स्थान में इन उप-केन्द्रों में से एक को स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य के लिए विश्वविद्यालय पिथौरागढ़ जिले के मनस्यारी तहसील में करीब 100 एकड़ फार्म प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है।

यह अनुसंधान उप-केन्द्र रानीचौरी के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र के परीक्षण तथा प्रमाणीकरण केन्द्र के रूप में कार्य करेगा। यह कृषि की महत्वपूर्ण समस्याओं पर अनुसंधान भी करेगा।

7025. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मंत्री यह

विश्वविद्यालय से उप-केन्द्र के सम्बन्ध में एक

विस्तृत परियोजना प्रस्ताव आने की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में वनरोपण तथा भू-क्षरण नियंत्रण योजनाएं

7626. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए मंजूर की गई विभिन्न वन-रोपण तथा भू-क्षरण नियंत्रण योजनाओं (विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा प्रायोजित) के नाम क्या हैं ; और

(ख) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विश्व बैंक से वित्तीय सहायता के लिए गत दो वर्षों के दौरान, "हिमालय क्षेत्र जल विभाजक" प्रबन्धक परियोजना, उत्तर प्रदेश" नामक एक परियोजना मंजूर की गयी थी। इस परियोजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में नयार और सरयू के दो जल विभाजक आते हैं।

(ख) इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

हिमालय क्षेत्र जल विभाजक प्रबन्ध परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य वन संरक्षण की क्षीणता, अधिक चराई; घटिया भू-उपयोग तथा लापरवाही से सड़क निर्माण के द्वारा हिमालय क्षेत्र के चुनींदा क्षेत्रों की पारिस्थितिकी पद्धति में होने वाले और ह्रास को कम करना है। इन सभी कारणों से इन क्षेत्रों में मृदा कटाव में वृद्धि हुई है। कार्यक्रम की विस्तृत विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(1) सरकारी तथा निजी स्वामित्व वाली,

दोनों प्रकार की भूमियों में ईंधन, इमारती लकड़ी और चारा उत्पादन के लिए मिश्रित प्रजातीय बागानों की स्थापना।

- (2) वर्तमान सड़कों की सुरक्षा करने तथा कृषि योग्य भूमि का संरक्षण करने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाने जैसे मृदा संरक्षण उपायों को शुरू करने के लिए मृदा संरक्षण और संरचनाओं का निर्माण।
- (3) पशुधन विकास तथा पशु आदान-प्रदान कार्यक्रम जिसके जरिए निकायें तथा अनुत्पादक पशुओं को उत्पादक भैसों के साथ 2-1 की दर से बदला जाता है। ताकि पशुओं की संख्या कम हो तथा उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो। इस प्रकार बदले गए पशु पहाड़ी क्षेत्रों से गोसदनों को लाये जाते हैं।
- (4) कृषि विस्तार सेवाओं का सुधार।
- (5) उद्यान विकास।
- (6) छोटी जल वाटिकाओं के निर्माण तथा उन्हें पक्का बनाकर तालाबों का निर्माण करके सिंचाई विकास।
- (7) जल विकास से संबंधित अनुसन्धान और प्रशिक्षण का विकास।

इस परियोजना के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में नयार और सरयू जल विभाजक आते हैं तथा इसमें दीर्घ हिमालय नदी पद्धति (ऊपरी गंगा) के श्रवण क्षेत्र बनते हैं। कुल जल विभाजक क्षेत्र 312,000 हैक्टर है। सात वर्षों की अवधि में 66 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से विश्व बैंक की सहायता करीब 46 करोड़ रुपये होगी।

करार पर 8 जून, 1983 को हस्ताक्षर किये गये थे। परियोजना लागू की जा रही है।

पनार नदी परियोजना

7627. श्री हरीश रावत : क्या सिंचाई मंत्री